प्रेस विज्ञप्ति
05/12/2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई आंचलिक कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत सुरेश पारेख, दिनेश पारेख, मनोज बियाणी, परेश शाह, रहीम हट्टीवाले, अरविंद लड्डा और अन्य आरोपियों की 16.42 करोड़ रुपये की अचल और चल संपत्तियां अनंतिम रूप से कुर्क की हैं।

ईडी ने विश्रामबाग पुलिस स्टेशन, सांगली द्वारा आईपीसी, 1860 की धारा 420 के तहत फर्जी संस्थाओं मेसर्स त्रिशूल एंटरप्राइजेज और अन्य के खिलाफ दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की, जिसमें आरोप लगाया गया था कि ये फर्जी संस्थाएं पूरे महाराष्ट्र में विभिन्न संस्थाओं को 458.24 करोड़ रुपये के फर्जी बिक्री बिल जारी करने में शामिल थीं और इनके द्वारा 28.34 करोड़ रुपये का वैट नहीं चुकाया गया, जिससे आईपीसी, 1860 की धारा 420 के साथ महाराष्ट्र मूल्य वर्धित कर, 2002 की धारा 34 के तहत दंडनीय अपराध हुआ।

ईडी की जांच में पता चला है कि 17 गैर-वास्तविक संस्थाओं का उपयोग करके 919 करोड़ रुपये के नकली चालान बनाए गए थे। उनके द्वारा बनाए गए नकली/फर्जी बिलों के संबंध में कभी भी माल की वास्तविक बिक्री या खरीद नहीं की गई थी। ये फर्जी संस्थाएं नकली व्यक्तियों के नाम पर खोली गई थीं और इनका नियंत्रण मनोज बियानी, परेश शाह, रहीम हट्टीवाले, अरविंद लड्डा और ऋषिकेश लड्डा द्वारा किया जा रहा था। सुरेश पारेख, दिनेश पारेख और सुशांत लड्डा पूरे वैट घोटाले के सरगना थे और सभी संस्थाओं और व्यक्तियों को नियंत्रित करते थे। इस तरीके से, नकली बिलों के मूल्य का 2% कमीशन, जिसकी राशि 18.67 करोड़ रुपये थी, सुरेश पारेख, दिनेश पारेख और सुशांत लड्डा द्वारा अर्जित की गई थी, जिसे बाद में वितरित किया गया था। इस प्रकार अर्जित कमीशन अपराध की आय है जो नकली बिक्री बिल जारी करने के अनुसूचित अपराध से संबंधित आपराधिक गतिविधि के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुई है।

इससे पहले, 23.06.2023 को सभी प्रमुख आरोपियों के आवास पर तलाशी अभियान चलाया गया था। इसके अलावा, तलाशी कार्रवाई के दौरान, 59.5 लाख रुपये की अस्पष्टीकृत नकदी के साथ-साथ विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए, जिससे आरोपियों द्वारा अपनाई गई कार्यप्रणाली का पता चला।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।